In the third session discussions were held on the future plans and programmes of Rachnatmak Shikshak Mandal. It was decided to hold the next workshop in Dehradun on Dec. 25-26, 2012

Total expenses of the Workshop was born by the Teachers' contribution which was Rs. 25,000 only.

- Navendu mathpal
Convenor, Rachnatmak Shikshak Mandal, Uttarakhand
Mobile : 09410373108, e-mail : mathpal@gmail.com
(English Translation by Dr.V.N.Sharma)

Itarsi, May 21, 2012

The status of education: Challenges and solutions

Discussion hosted by Shiksha Adhikar Manch, Hoshangabad

Participants included students, teachers, social workers and public intellectuals.

Summary of lecture by Anil Sadgopal:

Until the Common School System (CSS) is instituted, public education will not improve. Until the commodification of education is stopped, the common school system will not be viable. By supporting the privatization of education, we are denying all of our children a meaningful/equitable and quality education. The 25% reservations provision will not meet the demand for education. An estimated 2.5 crore children enter primary school every year. The 25% reservations will only affect approximately 20 to 25 lakh fortunate children. What will happen to the rest?

Less than 5 % of schools in Canada are private. Public education is paid for by public resources and rich and poor children study in the same school. It is a decentralized system where the cost is borne by local government but they do not have control In California, USA, schools with large numbers of poor children have larger budgets, more teachers, and more resources. It is the reverse in India where poor and disadvantaged children receive the worst education. In the state of Madhya Pradesh, poor and Adivasi children are guaranteed to receive the lowest possible quality of education.

All persons receiving public resources (salary, profit) in any capacity should be required to send their children to government schools then government schools will improve.

The challenge is not implementation but the law itself. It is not possible and even dangerous to try to implement a flawed law. People need to be educated, mobilized and organized.

Comments by other speakers

Teacher union representative Rajiv Dube spoke about the deterioration of conditions in government schools. Rajiv Bamne from Khesla discussed the challenges starting from Class I to B. Ed programmes. Teacher Deepali Sharma shared that when she was in government school she studied with the children of judges and officers. The quality of education was such that nobody needed tuition.

-Rajesh Vyas
President, District Forum for Right To Education, Hoshangabad
Translated from Hindi by Nisha Thapliyal
(nthapliyal74@gmail.com)

Bhopal, 19 May 2012

Right To Education, Order of the Supreme Court & Struggle for Common School System

Shiksha Adhikar Manch, Bhopal, All India Revolutionary Students' Organisation and Revolutionary Youth Federation of India organized a panel discussion on the Right To Education, Order of the Supreme Court & struggle for Common School System. The principal speakers included noted author Ms. Jyotsna Milan, (retd.) IAS officer Sri Sharad Chandra

Behar, well-known educationist and social activist Dr Anil Sadgopal, social worker Ms. Shivani Taneja, and RYI member Sri Vijay Kumar. The students, teachers and social activists of various educational and social organizations took part in the discussion.

Bhopal, June 11-16, 2012

Preparatory Workshop for 'Building Common School System & Abolishing Commercialization of Education

The State Platform for Common School System, Tamil Nadu and All India Forum for Right To Education will be holding a two-day All India Conference on 'Building Common School System & Abolishing Commercialization of Education' in Chennai on June 30-July 01, 2012. The preparatory workshop held in Bhopal on June 11-16, 2012 included participants from Lok Manch, Delhi, Basti Jan Sangathan, Bhopal, and Muskan. Cultural materials, plays and posters and related activities to be held in Chennai during the Conference were prepared with focus on the Right to Education and Common School System.

Translated from Hindi by Nisha Thapliyal (nthapliyal74@gmail.com)

कैसे सुधरें सरकारी स्कूल

अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा के लिए बने कानून (आरटीई) पर उच्चतम न्यायालय ने भी मुहर लगा दी है। सिर्फ इस संशोधन के साथ कि यह कानून गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। इस सब के बाद भी क्या देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो जाएगी? आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि ऐसा होता नहीं दिख रहा। कारण यह है कि अब भी 75 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं जिनकी स्थिति में सुधार के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया जा रहा। निजी स्कूलों में तो सिर्फ 18 प्रतिशत बच्चे पढ़ते हैं। शेष अनुदानित स्कूलों में हैं। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के जिन बच्चों का दाखिला होगा वह कुल बच्चों की संख्या का महज 5 से 6 प्रतिशत ही होगा। शेष बच्चों को तो सरकारी स्कूलों में ही जाना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि अधिकतर निजी स्कूल शहरी इलाकों में हैं। इनका हिस्सा ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 9.3 प्रतिशत ही है। ऐसे में यह तय है कि आरटीई के तहत अच्छे निजी स्कूलों में सिर्फ शहरी या बड़े कस्बों के वंचित वर्ग के बच्चों को ही प्रवेश मिल सकेगा। गांवों में तो 6 से 14 वर्ष के अधिकतर बच्चे सरकारी स्कूलों के भरोसे ही रहेंगे।

ऐसे में जरूरी है कि उन सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माहौल तैयार किया जाए जहां पर्याप्त कक्ष नहीं होते। कक्ष हैं तो शिक्षकों की संख्या पूरी नहीं है, शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आते, आते भी हैं तो पढ़ाते नहीं। यह किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। कमोबेश सभी राज्यों में सरकारी स्कूलों का हाल एकसमान है। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने निर्णय में कहा है कि सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक होने के बावजूद वहां शिक्षा का स्तर निजी स्कूलों जैसा नहीं है। साथ ही न्यायालय ने सरकारों को इन सरकारी स्कूलों पर ध्यान देने को भी कहा है।

कैसे सुधरे सरकारी स्कूलों की दशा

- सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराना अनिवार्य हो।
- सरकारी स्कूलों को भवन, शौचालय, साफ पानी, कुर्सी-मेज जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण बनाया जाए।
- सरकारी स्कूलों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षकों की संख्या तय की जाए और इन पदों को भरा जाए।
- सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की वेतनवृद्धि को उन स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाए।
- सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से बच्चों की तमाम [illegible] न कराई जाए, न ही उनको जनगणना, पल्स पोलियो जैसे अभियानों में लगाया जाए। पाठ्यक्रम भी सुधारा जाए।

क्या निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश देने भर से देश में सभी को शिक्षा का लक्ष्य हासिल हो जाएगा? यदि नहीं, तब फिर क्या है इलाज? इलाज यही है कि देश के तमाम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट के जैसा बनाया जाए। इसके लिए जरूरी है कि देश-प्रदेश के राजनेता और अफसरों के बेटे-बेटी कम से कम पांचवीं कक्षा तक सरकारी स्कूल में पढ़ें।

शिक्षा का अधिकार: निजी स्कूलों में तो सिर्फ 18 प्रतिशत बच्चे ही पढ़ते हैं। शेष को सरकारी स्कूलों में ही जाना होता है, इसलिए सरकारी स्कूलों की दशा सुधारी जानी चाहिए।

स्कूलों की स्थिति

स्कूल का प्रकार	कुल संख्या में हिस्सा	विद्यार्थियों में हिस्सा	प्रति स्कूल शिक्षक
सरकारी	80.2	75.4	3.9
अनुदानित	5.8	6.7	8.3
गैर अनुदानित निजी	13.1	17.8	6.7

वर्ष 2007-08 में प्रा एवं उच्च प्रा स्कूल 12,50,775

मध्य प्रदेश	राजस्थान
निजी स्कूल 22,568	निजी स्कूल 34,207
दर्ज बच्चे 48 लाख	दर्ज बच्चे 42.60 लाख
गरीब जो दाखिला ले सकेंगे 12 लाख	गरीब जो दाखिला ले सकेंगे 10.6 लाख
सरकारी स्कूल 1,11,000	सरकारी स्कूल 72,437
दर्ज बच्चे 1 करोड़ 7 लाख	दर्ज बच्चे 80.02 लाख
(कक्षा एक से आठ तक की स्थिति)	(कक्षा एक से आठ तक की स्थिति)

यह भी कहा न्यायालय ने

- [illegible] आरटीई की धारा 12(3) [illegible]
- [illegible] अनुच्छेद 19 (1)(जी) [illegible]
- [illegible] आरटीई के तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों के प्रवेश का प्रावधान [illegible]
- 14 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करना बच्चे का अधिकार है। [illegible]
- [illegible]